

[Shri Ravindra Varma]
pending for discussion and a tentative schedule of the Ministries that will come up for discussion has been circulated, the Minister of Parliamentary Affairs does not make a statement. There has, therefore, been no departure from the past precedents.

The hon. Member raised the question of the possibility of some changes in dates depending upon the availability of the hon. Ministers concerned. If there is to be any such change, the House will be notified in due course.

12.48 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED STRIKE IN KHETRI COPPER PROJECT

श्री माधु सिंह (दासा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति में सदन का ध्यान एक अन्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर धारुष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 25 फरवरी से खेतड़ी ताबा प्रोजेक्ट के लगभग 8 हजार मजदूर पूर्णतः हड़ताल पर हैं जिससे वहाँ का उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है। मजदूरों को पिछले कई दिनों में वेतन नहीं मिल रहा है। होनी नजदीक है। ऐसे प्रवसर पर मजदूरों को वेतन व मिलने से उन में व उनके परिवार के सदस्यों में घोर निराशा उत्पन्न हो गई है। उसमें बहातनाव की स्थिति बनती जा रही है। कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने मंत्री महोदय में मिलकर हल निकालने का भी प्रयत्न किया लेकिन असफल रहे। वैसे हड़ताल मजदूरों द्वारा प्रारम्भ नहीं की गई थी बल्कि प्रबंधकों द्वारा कराई गई थी। बात केवल रस्ता बदलने की थी। जिस रस्ते के द्वारा मजदूर खान में जनरते है उसको सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने जाव के दौरान ठीक नहीं समझा व प्रबंधकों को उस रस्ते को बदलने की सलाह दी लेकिन रस्ता नहीं बदला गया। तब मजदूरों ने अपनी जान बचाने के लिए यही उचित समझा कि बिना रस्ता बदले अर्थात् इस पुराने रस्ते के सहारे नीचे खान में नहीं उतरा जाये। जब फिर भी रस्ता न बदला गया तो मजदूरों ने नीचे जाने से

इनकार कर दिया और पांच वर्ष पूर्व से चली आ रही कुछ और मार्गों को साथ जोड़कर मैनेजमेंट से बात करने की इच्छा प्रकट की। मगर मैनेजमेंट ने खान करने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी से वहाँ हड़ताल प्रारम्भ हो गई। कई संसद सदस्य वहाँ गये। मैं स्वयं भी वहाँ गया। वहाँ के मजदूरों से बातचीत की। हड़ताल होने से लाखों रुपये का देश को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी चाहते है कि वहाँ उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाये, दो वर्ष से कार्य कर रहे मजदूरों को स्थायी किया जाये, बोलस दिया जाये एवं कपडे जो कि नीचे खान में जाने से खराब हो जाते हैं, मजदूरों को दिये जायें। अर्थात् वर्गों देने की व्यवस्था की जाय— ये सब उन मजदूरों की समस्यायें हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये समस्यायें बहुत कठिन नहीं हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखाते हुए, वे उनसे बातचीत करे और उचित मार्गों को स्वीकार करे, तथा अन्य मार्गों पर विचार करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त करे, ताकि हड़ताल समाप्त हो सके, कर्मचारियों का असन्तोष समाप्त हो और वहा पर पुनः उत्पादन प्रारम्भ हो सके।

मैं मंत्री महोदय से पुनः कहना चाहंगा कि उन मजदूरों की समस्याओं पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने के लिए उन्हें यहाँ बुलायें या स्वयं वहाँ पर जायें और बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल निकालें, ताकि देश नुकसान से बच सके और उन कर्मचारियों को कुछ दिया जा सके, जिससे उनका असन्तोष समाप्त हो।

(ii) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF MOGUL LINES CAUSING HARDSHIPS TO PASSENGERS GOING TO KONKAN.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I rise here to raise a matter of urgent public importance in this House under Rule 377. Operation

of ships on West Coast of Konkan was done by Bombay Steam Navigation Company and by M/s. Chougule Steamship Company prior to 1973. This service was nationalised in 1973. Prior to nationalisation, ships of Bombay Steam Navigation Company used to call at 20 ports and that of Chougule Steamship used to call at 16 Ports. After nationalisation, ships are operated by Mogul Lines and since October, 1977, ships of Mogul Lines are calling on at four ports on this line. Employees of Mogul Lines are reported to have gone on strike since Monday, the 20th March, 1978. This is the peak season of the traffic of the year. The people of Konkan living in Bombay want to rush to their respective homes for Holi festival and because of the strike, considerable inconvenience will be caused to them. I, therefore, request the Minister and the Government to take immediate action in the matter to end the strike and direct Mogul Line to meet the demands of the employees and in the meantime, make alternative arrangement to operate the ships and avoid inconvenience that is being caused to passengers.

(iii) REPORTED KIDNAPPING OF TWO
GIRLS OF RAMA KRISHNA PURAM,
NEW DELHI.

श्री सुबराज (कटिहार). अध्यक्ष महोदय, आज नारे दिल्ली शहर की जनता में बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना व्याप्त है। यह घटना 15 मार्च की है, धार० के ० पुरम गल्ले हायर सेनेण्डरी स्कूल की छात्रा—नन्दिता मजूमदार और पंछी रावत, जो 9वीं क्लास में पढ़ती थीं, जब घर वापस आ रही थीं तो रास्ते में इन दोनों छात्राओं को किडनेप कर लिया गया और इन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेस्ट हाउस में रखा गया। दूसरे दिन पंछी रावत घर वापस आ गईं, लेकिन जब नन्दिता मजूमदार (कमा) चार-पांच दिन तक घर नहीं लौटी तो बिजल सरकार जो एक नर्नमेंट-पार्टी शिवल भी हैं, हमारे माननीय सदस्य श्री पूर्ण सिन्हा के यहाँ गए और उन से निवेदन

किया कि मेरी लड़की जो बिचासय से पढ़कर घर वापस आ रही थीं, रास्ते में गायब कर ली गईं। माननीय सदस्य श्री पूर्ण सिन्हा जी ने एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखा—अगर 24 घण्टे के भीतर नन्दिता मजूमदार को बरामद नहीं किया जा सकेगा तो हम इस सवाल को लोक सभा में उठावेंगे। श्री बिजल सरकार प्रधान मंत्री जी के यहाँ भी गए थे। दो दिन बाद यानी ता० 21 को नन्दिता मजूमदार बरामद हुई।

आप को यह जान कर आश्चर्य होगा—जब श्री बिजल सरकार पुलिस में गए और उन्होंने पुलिस अफसर से निवेदन किया कि यह हमारी लड़की का फोटो है, इसको अखबार में निकलवा दो और इस की छानबीन करो। तो पुलिस आफिसर ने रिफ्यूज किया इसलिए कि पुलिस आफिसर का एक रिजल्टिव इस मामले में जिम्मेदार था? यही वजह थी कि लड़की छुपा कर रखी गई थी और जब उन से इस बारे में कहा गया तो उन्होंने झगड़ती कर दी लेकिन जब माननीय सदस्य ने इस का नोटिस लिया और उन्होंने गृह मंत्री जी को लिखा तब जा कर लड़की बरामद हुई। आप यह जानते हैं कि आजकल दिल्ली में फाइम बढ़ रहे हैं और किसी धावनी की इज्जत महफूज नहीं है। किस की लड़की कहां और कब गायब हो जाए, इस का ठिकाना नहीं है।

इस घातकपूर्ण स्थिति की धोर में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

12.56 hrs.

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL—Contd.

MR. SPEAKER: We take up further Clause-by-Clause consideration of the Public Sector Iron and Steel (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill.